सम्पूर्ण आजादी का दस्तावेज

डाईवर्सिटी

डायर बुक : 2013-14

संपादक : एच.एल. दुसाध
सह-संपादक : कविश कुमार-विनय कुमार

डाइवर्सिटी इयर-बुक

2013-14

सम्पादक

एच.एल. दुसाध

सह-सम्पादक

कविश कुमार - विनय कुमार

प्रथम संस्करण : ....

ISBN : 978-81-87618-46-1

बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के लिए
द्वारा
प्रकाशक : **दुसाध प्रकाशन**
डाइवर्सिटी हाउस, वार्ड-शंकरपुरवा
आदिल नगर, कल्याणपुर, लखनऊ-226022
E-mail : hl.dusadh@gmail.com
मो. : 9313186503, 9696252469

प्रशासनिक कार्यालय
एफ-196, आया नगर एक्स, फेज-6, नई दिल्ली-110047,
मो. : 9313186503

© **संपादक**

मूल्य : 1100.00 रुपये

रचना	:	**डाइवर्सिटी इयर-बुक : 2013-14**
संपादक	:	एच.एल. दुसाध
आवरण	:	शशिकान्त
शब्दांकन	:	कम्प्यूटेक सिस्टम, शाहदरा, दिल्ली-32
मुद्रक	:	क्विक ऑफसेट, दिल्ली-94

डाइवर्सिटी इयर बुक

2013-14 का संपादकीय परिवार

संरक्षक : **डॉ. संजय पासवान**

प्रेरणा मण्डल : **दिग्विजय सिंह, चन्द्रभान प्रसाद, सुधीन्द्र कुलकर्णी, डॉ. जगदीश प्रसाद, छेदी पासवान, डॉ. एस. एन. संखवार, डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल, सुरेश केदारे, डॉ. संजय वठारे**

मुख्य परामर्शदाता : **बुद्ध शरण हंस, दिलीप मंडल**

परामर्श मण्डल : **बृजपाल भारती, प्रो. आई.जे. सिंह, आर.सी. कैथल, डॉ. विजय कुमार त्रिशरण, के.सी. मेश्राम, अभिजीत कुमार, डॉ. जय प्रकाश कर्दम, सुदेश तनवर, विरेन्द्र कुमार, डॉ. पी. एल. संखवार, आर.सी. भाष्कर, आशिक भागलपुरी, कौशलेन्द्र प्रताप यादव, नागेन्द्र कुमार, डॉ. सुदर्शन प्रसाद, निर्मल पासवान**

संपादक : **एच.एल. दुसाध**

सह-संपादक : **कविश कुमार - विनय कुमार**

संपादक मण्डल : **शीलबोधि, डॉ. चन्द्रशेखर राम, ललन कुमार, अनिल कुमार आर्य, राम किशोर यादव, डॉ. अमरनाथ, बाबूलाल मधुकर**

संपादकीय संपर्क : **एच.एल. दुसाध**
एफ-196, आया नगर एक्स, फेज-6
नई दिल्ली-110047
मो. 9313186503, 9696252469

समर्पण

विविधता के प्रति गहरा सम्मान रखने वाले

राजनीति शास्त्र के प्रकांड विद्वान

*प्रो. **रमेश दीक्षित** को*

सम्पादकीय

2006 से शुरू हुआ डाइवर्सिटी इयर बुक का सफर 2013 तक पहुँच चुका है। किन्तु विगत दो वर्षो की भांति इस बार भी इसे निर्दिष्ट तिथि (27 अगस्त) को प्रकाशित करने हम व्यर्थ रहे। इसका कारण यह है कि जिस 'डाइवर्सिटी डे' के अवसर पर इसका प्रकाशन होता है,वही समय पर नहीं हो पा रहा है। 2011 में 16 अक्तूबर को जबकि 2012 में 30 सितम्बर को इसका आयोजन हुआ। इस बार भी कुछ अत्याज्य कारणों से 27 अगस्त को आठवे डाइवर्सिटी का आयोजन नहीं हो पाया। किन्तु बिलम्ब होने पर भी आयोजनों की गरिमा में कहीं से कमी नहीं आई। इस मामले में तो 2012 का आयोजन बहुत खास ही रहा। विश्व कवि नामदेव ढसाल और उनके संगठन 'दलित पैंथर'के सौजन्य से मुंबई में आयोजित सातवें डाइवर्सिटी की सुखद यादे आज भी हमारे जेहन में हैं और ताउम्र रहेंगी। आंबेडकरी आंदोलन के अप्रतिम नायक ढसाल साहब के साथ मंच शेयर करना बीडीएम के लिए एक उपलब्धि जैसी रही। बहरहाल आज जबकि हमेशा की तरह ही गत एक वर्ष का इतिहास रिकार्ड करने बैठे हैं, मन में उत्साह नहीं है। कारण पिछला एक वर्ष,यदि उत्तर प्रदेश के बहुजन छात्र आन्दोलन को अपवाद मान लिया जाय तो बहुजन भारत के लिए उत्साहवर्द्धक नहीं रहा। इसका खास कारण हैं बहुजन नेतृत्व की सवर्णपरस्ती। सवर्णपरस्ती की होड़ में एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में उन्होंने शक्ति के स्रोतों बहुजनों की भागीदारी के मामले को पूरी तरह भुला दिया। इसका सबसे बड़ा खामियाजा प्रोन्नति आरक्षण विधेयक को भुगतना पड़ा, जिसके विषय में पिछले इयर बुक की सम्पादकीय में इसका हस्र महिला आरक्षण विधेयक जैसा होने की आशंका व्यक्त किया था। इस विधेयक की पिछले एक साल की प्रगति देखकर लगता है कि हमारी आशंका सही होने जा रही है। पिछले एक साल में जहां बहुजन नेतृत्व ने समाज को निराशा गर्त में धकेला, वहीं सवर्णवादी न्यायपालिका, मीडिया और उसके युवा वर्ग की सक्रियता समाज को आतंकित की। इस लिहाज से गत दिसंबर में घटित दिल्ली गैंग रेप की घटना ने मध्यम वर्ग के युवाओं और मिडिया को अपनी ताकत दिखाने का बड़ा मंच दे दिया।

दिल्ली गैंग रेप : राष्ट्र ने खोया महिला सशक्तिकरण का स्वर्णिम अवसर

दिल्ली गैंग रेप के पीछे लामबंद मध्यम वर्ग के युवाओं का लक्ष्य बलात्कार का खात्मा नहीं,भविष्य के सत्ता दखल का रिहर्सल मात्र था। यह इस बात से भी साबित होता है कि दिल्ली गैंग रेप के बाद शहरों-कस्बों से लेकर दूर-दराज के गाँवों में दलित बच्चियों-महिलाओं के साथ रेप की ढेरों जघन्य घटनाएं हुईं,पर मध्यम वर्ग के युवा खामोशी धारण किये रहे। उनकी खामोशी तब टूटी जब गत अगस्त माह में मुंबई के एक परित्यक्त कपड़ा मिल में एक पत्रकार युवती के साथ रेप की घटना हुई। शायद वह युवती उन्हें निज वर्ग की लगी। किन्तु इसी अगस्त के उत्तरार्द्ध में उस घटना के कुछ दिनों बाद जब संत आसाराम पर उनके ही आश्रम की एक नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार का आरोप लगा, कैंडिलबाज आन्दोलनकारी पता नहीं कहाँ दुबक गए। लगभग दो सप्ताह तक पुलिस को छकाने के बाद जब यह बाबा गिरफ्तार हुआ,उसके अनुयायी तो उसे बचाने के लिए सड़कों पर उतरे,किन्तु दिल्ली गैंग रेप के खिलाफ विजय चौक को तहरीर चौक में तब्दील करने वाले गायब रहे। आज जबकि एक-एक करके इस बाबा के शर्मनाक कारनामें सामने आ रहे हैं,युवा वर्ग के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती दिख रही है। ।

दरअसल यह मध्यम युवा वर्ग देश की किसी भी समस्या के प्रति गंभीर नहीं है,ऐसा 2011 से ही दिख रहा है, जब वह एक 7 क्लास पास एक दकियानूस गांधीवादी के पीछे भ्रष्टाचार विरोधी मुहीम में शामिल हुआ था। उस बार भी उसने छोटे-मोटे तहरीर चौक की अवतारणा की। उस बार उसने भेड़चाल की तरह सिर्फ जनलोकपाल की मांग की,पर एक बार भी धन-तृष्णा ,जो भ्रष्टाचार का मूल है, के पीछे क्रियाशील आकांक्षा-स्तर और उपलब्धि अभिप्रेरणा जैसे सामाजिक मनोविज्ञान से जुड़े कारकों की तफ्तीश करने की कोशिश नहीं की। क्या वह अबोध था जो अनपढ़ हजारे और केजरीवाल जैसे एनजीओबाजों का अन्धानुसरण करने लगा ?नहीं चालाक युवा वर्ग ने समझ लिया था यदि सामाजिक विविधतारहित जनलोकपाल लागू होता है तो बहुजन समाज की भारतीय लोकतंत्र पर पकड़ ढीली हो जाएगी और कालांतर में वे उसे अपहृत कर लेंगे। 2011 की भांति ही 2012 में मानवता को शर्मसार करनेवाली घटना के पीछे क्रियाशील सामाजिक मनोविज्ञान को समझने का जरा भी प्रयास नहीं किया। बस आरोपियों को नपुंसक बनाने और फांसी जैसी कठोर सुनाये जाने की मांग करता रहा। हालाँकि उसके आंदोलित होने के दौरान बलात्कार की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई। ऐसे में कठोर दंड की मांग के साथ उसे बलात्कार के पीछे क्रियाशील मनोवैज्ञानिक कारणों की अवश्य ही चर्चा करनी चाहिए था। किन्तु ऐसा करता तब न, जब उसे महिलाओं की समस्यायों के प्रति संवेदना होती। उसे तो सिर्फ कठोर दंड की सजा का प्रावधान कराकर बस अपनी ताकत की आजमाइस करनी थी,

जिसमें वह सफल रहा। निर्भया के नाम पर बजट पास होने तथा दिल्ली गैंग रेप के आरोपियों को फांसी की सजा सुनाएँ जाने की घटना बताती है की वह अपने लक्ष्य में कामयाब रहा। रेप के खिलाफ आंदोलित होने की उसकी मंशा को समझने के लिए अध्याय तीन के 'मध्यम वर्ग को चाहिए अपनी एक पार्टी' तथा 'भारतीय राज्य पर कब्जा जमाने का भयावह मंसूबा' पढ़ने के लिए खास तौर से आग्रह कर रहा हूँ।

विश्व के सर्वाधिक शक्तिहीन समुदायों में एक भारतीय महिलाओं के जीवन में दिल्ली गैंग रेप के खिलाफ उमड़ा जनाक्रोश सुखद बदलाव ला सकता था, यदि आन्दोलनकारियों ने यह उपलब्धि किया होता कि उनकी सारी समस्या की जड़ शक्ति के स्रोतों (आर्थिक-राजनितिक-धार्मिक) में न्यूनतम भागीदारी है। ऐसी सत्योपलब्धि करने के बाद यदि शक्ति स्रोतों में लैंगिक-विविधता लागू करने की मांग उठती और शासक दल के लिए उस मांग को खारिज करना कठिन होता। यह मांग पूरी होने पर भारतीय समाज हजारों साल से महिलायों पर किये गए अत्याचार,शोषण इत्यादि का प्रायश्चित कर लेता। ऐसा अवसर भारतीय नारी के जीवन कब आएगा कहना मुश्किल है। ऐसे में कहा जा सकता है राष्ट्र ने महिला सशक्तिकरण का एक स्वर्णिम अव्सर खो दिया।

अमेरिकी बनाम भारतीय प्रभुवर्ग

व्हाईट हाउस में दोबारा ब्लैक ओबामा का पहुंचना दुनिया भर में जन्मगत कारणों से शक्ति-के स्रोतों से वंचित किये गए लोगों के लिए भारी हर्ष का विषय रहा। वैसे तो उनकी विजय के पीछे एकाधिक कारण रहे किन्तु सबसे बड़ा कारण अमेरिकी प्रभुवर्ग का सामाजिक विवेक ही रहा। (पढ़ें अध्याय चार का लेख-'अमेरिकी प्रभुवर्ग के सामाजिक विवेक की एक और विजय')। यह सामजिक विवेक ही वहां के गोर प्रभुवर्ग को लम्बे समय से अपने पुरुखों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए ,कालों के हित में समय-समय पर व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से कुछ बेमिसाल कदम उठाने की प्रेरणा देता रहा है। इस कारण ही कभी दलितों से भी बदतर स्थिति में रहनेवाले ओबामा के पुरुखों की वर्तमान पीढ़ी शक्ति के स्रोतों में वाजिब भागीदारी मिली। इस कारण ही वहां कालों में रॉबर्ट एल जॉनसन ,जैनिक्स ब्रायंट जैसे बिलियनेयर उद्योगपति; ओपरा विनफ्रे, एडी मर्फी जैसे टीवी एंकर; डेंजिल वाशिंग्टन, विल स्मिथ, हैलेबेरी, हूँपी गोल्डबर्ग जैसे फिल्म सितारों और रास्पबेरी जैसे पत्रकार सहित विभिन्न क्षेत्रों में ढेरों नायकों का उदय हुआ। बाकी था राजनीति का क्षेत्र। हालाँकि यहाँ भी कॉलिन पॉवेल,कोंदजिला राईस इत्यादि थे ,पर ओबामा जैसे किसी सितारे नेता की कमी खल रही थी। इस कमी को वहां के गोरों 2009 के चुनाव में पूरा कर दिया। गोरों से मिले अवसर का रॉबर्ट एल जॉनसन, ओपरा विफ्रे, विल स्मिथ इत्यादि

की भांति ही ओबामा ने भी जमकर सद्व्यवहार करते हुए प्रमाणित कर दिया कि उपयुक्त अवसर मिलने पर नर-पशु भी योग्यता का सर्वोच्च निदर्शन स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने जिस शानदार अंदाज में पहली पारी में राष्ट्रपति के रूप में अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन किया, उससे उन्हें दोबारा व्हाईट हाउस में पहुचने का मौका मिलना ही था। पर, सवाल पैदा होता है अगर गोरे अपने सामाजिक विवेक का परिचय नहीं दिए होते तो 28 प्रतिशत अश्वेतों, जिसमें काले सिर्फ 13 प्रतिशत हैं,के प्रतिनिधि ओबामा क्या 70 प्रतिशत से अधिक आबादी के प्रतिनिधि मिट रोमनी को हारा पाते?

एक तरफ अमेरिका है जहाँ का प्रभुवर्ग वहां के दलितों पर 400 वर्ष पूर्व किये गए शोषण-उत्पीड़न का प्रायश्चित करने के लिए के लिए उन्हें मुक्त-हृदय से सभी क्षेत्रों में अवसर देकर प्रतिनिधित्व पर आधारित अपने डेमोक्रेसी को आइडियल रूप प्रदान कर रहा है। दूसरी तरफ भारत का प्रभुवर्ग है जिसमें साढ़े तीन हजार पूर्व शक्ति के तमाम स्रोतों से निर्ममता से वंचित किये गए नर-पशुओं को उनका लोकतान्त्रिक हक तक देने की मानसिकता विकसित नहीं हो पाई। यह समस्या प्रोमोशन में आरक्षण की राह में एवरेस्ट बनने वाले 'सर्वजनहिताय संरक्षण समिति'के किसी शैलेन्द्र दुबे के साथ ही नहीं,नामवर सिंह जैसे प्रतिष्ठित विद्वान के साथ भी है। तभी तो हिंदी के अमिताभ बच्चन को यह कहने में कोई कुंठा नहीं होती कि यदि साहित्य में आरक्षण लागू होता है तो यह राजनीति की तरह गन्दा हो जायेगा। (देखें अध्याय 6 का लेख 'साहित्य अकादेमी में विविधता की जरुरत')। लेकिन दुबे और सिंहों की यह विवेकशून्यता बहुजनों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है तो न्यायपालिका में। (पढ़ें अध्याय 9 का लेख-'भारतीय आन्दोलनों से गायब रूमानव जाति का सबसे बड़ा मुद्दा')। सामाजिक- लैंगिक विविधता से पूरी तरह शून्य होने के कारण जिस शक्तिशाली संस्था को सबसे बड़ी गैर-लोकतान्त्रिक संस्था कहा जा सकता है,वह भारतीय लोकतंत्र को दुरुस्त करने के नाम पर ऐसे-ऐसे फैसले ले रही है जो बहुसंख्यक लोगों के हितों के बिलकुल खिलाफ है। इसका सारा आचरण देखकर लगता है कि बहुजन चेतना के कारण राजनीतिक रूप से लाचार बन चुके दुनिया के प्राचीनतम शक्ति व सुविधा-संपन्न जमात के शक्ति के स्रोतों पर एकाधिकार को अटूट रखने की यह अकेले लड़ाई लड़ रही है। लक्ष्मणपुर बाथे कांड पर इसका फैसला बहुजनों को सकते में डाला ही है,उप्र की पुलस की भर्ती प्रक्रिया में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश ने भी खलबली मचा दी है। इसमें स्पष्ट किया गया है संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत जिन जातियों का सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व पूरा हो गया है,उन्हें आरक्षण न दिया जाय। अगर इसी को दृष्टान्त बनाकर तमाम भर्तियों में यह नियम लागू हो जाता है फिर भारत में सामाजिक-न्याय की लड़ाई पर विराम लग जायेगा और परम्परागत शक्तिसंपन्न तबका अप्रतिरोध्य हो जायेंगा।

ऐसे और कई फैसले हैं जिससे बहुजन समाज उद्भ्रांत होकर न्यायपालिका में आरक्षण की आवाज जोर से बुलंद करने लगा है।

बहरहाल संसद के ऊपर हावी होती न्यायपालिका को संतुलित करने के लिए 'न्यायिक नियुक्ति आयोग'बनाने का प्रस्ताव आया है जो राज्य सभा में पारित भी हो गया है। यह प्रस्ताव संसदीय समिति के सुपुर्द भी कर दिया गया है। इस आयोग के छह सदस्य होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश ,उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश,केन्द्रीय कानून मंत्री और दो लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति। विधि एवं न्याय सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। हो सकता है यह आयोग बनने से बेलगाम होती न्यायपालिका पर अंकुश लगे। किन्तु जहाँ तक बहुजन समाज को न्याय मिलने का सवाल है यह तब तक नहीं मिल सकता जब तक लोअर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जजों ही नहीं पेशकारों की नियुक्ति तक में सामाजिक और लैंगिक विविधता लागू नहीं होती-

विविध भारत

प्रत्येक संस्था/समितियों में लागू हो सामाजिक और लैंगिक विविधता

पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय से संबद्ध राजमंत्री नारायण सामी ने यह कहकर राष्ट राष्ट्र को चौका दिया कि अब सरकार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानि कैग को चुनाव आयोग की तरह बहुसदस्यीय बनाने जा रही है। किन्तु विपक्षी दलों की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद सामी अपने बयान से पलट गए और मामला आया गया हो गया। लेकिन बुद्धजीवियों में यह चर्चा का विषय बन गया। अधिकांश बुद्धिजीवियों ने ही इसे बहुसदस्यीय बनाने पर जोर दिया। किन्तु राजनीतिक, साहित्यिक-सांस्कृतिक, वैज्ञानिक या व्यवसायिक किसी भी संस्था को व्यक्ति विशेष की तानाशाही से बचाने के लिए, उस संस्था को बहुसदस्यीय बना देना बेहतर जरुर हो सकता है, किन्तु सर्वोत्तम नहीं। कारण इन सदस्यों को चुनने/नियुक्त करने की शक्ति जिस व्यक्ति/दल में होगी वह अपनी पसंद के ही व्यक्ति को चयनित करेगा। लेकिन संस्था शासकीय हो या अशासकीय, अगर उसके द्वारा समग्र वर्ग का हित-पोषण करना है तो भारत जैसे समग्र वर्ग की चेतना से कंगाल देश में, उसको बहुसदस्यीय बनाने की बजाय उसमें सामाजिक और लैंगिक विविधता का प्रतिबिम्बन ही सर्वोत्तम विकल्प हो सकता है। ऐसा करने पर सबसे पहले तो संस्था का प्रजातांत्रीकरण हो जायेगा। दूसरा संस्था/समिति में शामिल महिलाएं और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि अपने-अपने समुदाय के हितों के लिए प्रयासरत रहेंगे। इससे जाति/वर्ण विशेष की बजाय संस्था सर्व-समाज के हित में कार्य करने के लिए बाध्य होगी। (देखें अध्याय 8 का लेख-सवैधानिक संस्थाओं में विविधता की जरुरत)।

नंदी का बयान भ्रष्टाचार उन्मूलन में हो सकता था सहायक

2013 के गणतंत्र दिवस के अवसर देश के महान समाज मनोविज्ञानी आशीष नंदी ने यह कहकर–यह तथ्य है कि ओबीसी और दलित सर्वाधिक भ्रष्टाचारी हैं और अब आदिवासी भी उसमें शामिल हो रहे हैं -बहुजन समाज को सकते में डाल दिया था। उनके बयान पर राष्ट्रव्यापी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। किन्तु कुछ दिनों तक चाय के प्याले में तूफान पैदा करने के बाद मामला पूरी तरह शांत हो गया। अब नंदी ने वैसा कुछ कहा था,शायद ही किसी को याद हो। बहरहाल नंदी ने जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में दलितों, पिछड़ों को सर्वाधिक भ्रष्टाचारी करार देकर, सर्वाधिक भ्रष्टाचारी कौन? चिन्हित करने का दुर्लभ एक मौका दे दिया था। इससे भ्रष्टाचार के जातिशास्त्र पर चर्चा होती। चर्चा आगे बढ़कर भ्रष्टाचार की जड़ धन-तृष्णा के पीछे क्रियाशील विभिन्न जातियों के आकांक्षा स्तर और उपलब्धि अभिप्रेरणा तक जाती । फिर पता चलता भारत के जाति समाज में राष्ट्र को हिला कर रख देने वाले घोटालों के पीछे 80-85 प्रतिशत हाथ सवर्णों का है। भ्रष्टाचारी चिन्हित होने के बाद उनपर अंकुश लगाने का कार्य होता। इस तरह भारत से भ्रष्टाचार के खात्मे का उपाय निकलता । किन्तु शायद मुख्यधारा के बुद्धिजीवियों को पता था कि भ्रष्टाचार के जाति-शास्त्र पर बहस उनके समाज को भ्रष्टाचारी वर्ग में चिन्हित कर देगी,इसलिए वे कन्नी काटने के साथ चुप्पी साध लिए। (पढ़े अध्याय 8 के लेख-1-भ्रष्टाचार की गंगोत्री : हिंदी पट्टी, 2-सर्वाधिक भ्रष्ट कौन!) चूँकि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के रास्ते हजारे-केजरीवाल और उनकी पार्टनर सवर्णवादी मिडिया का एकमेव लक्ष्य अल्पजन हित में भारतीय लोकतंत्र को हाइजैक करना रहा, इसलिए 2011 में उन्होंने भ्रष्टाचार के जाति शास्त्र पर चर्चा नहीं होने दिया। इसी तरह इस बार भी सवर्ण बुद्धिजीवियों ने मामले को भटका दिया। ऐसे में जब तक शक्ति के सभी स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता लागू नहीं हो जाती भारत से भ्रष्टाचार के खात्मे की उम्मीद बहुजन समाज को छोड़ ही देनी चाहिए। हां भ्रष्टाचार के खात्मे के नाम बहुजन नायकों को जेल भेजने का उपक्रम चलता रहेगा, इसकी मानसिक प्रस्तुति बहुजनों को ले लेनी चाहिए।

धन्यवाद मि. केजरीवाल

पिछले एक साल में बहुजन समाज के हित में जो थोड़ी सी अच्छी बातें हुईं उनमें है एक है केजरीवाल का राजनीति में आना। इस शातिर शख्स ने निरीह हजारे के साथ मिल कर भ्रष्टाचार के खात्मे की आड़ में लोकतंत्र को हाइजैक करने का बलिष्ठ प्रयास किया था। उसके अभियान से राष्ट्र के धन और समय की बेहिसाब हानि हुई थी। अगर वह अपना अभियान जारी रखता तो रह-रह कर राष्ट्र को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता। अच्छा हुआ कि भारतीय राज्य पर कब्जा जमाने

का पूर्वाभ्यास कर रहे सवर्ण युवाओं की भीड़ ने उसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा पैदा कर दिया और वह एमएलए ,एमपी बनने के लिए प्रयासरत हो गया । राजनीति में आने के बाद उसने पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर खुलकर सर्वजन हिताय समिति का समर्थन कर दिया। इससे उसका बहुजन विरोधी चेहरा और भी बेनकाब हो गया। अब आप चाहे तो इस राष्ट्र की किस्मत पर रो सकते हैं कि केजरीवाल जैसे तीसरे दर्जे का व्यक्ति मीडिया के सौजन्य से 'आप'का नेता होने का सपना देख सकता है। बहरहाल अपना असल रूप रूप उजागर करने के पुरस्कार स्वरूप केजरीवाल को धन्यवाद तो दिया ही जा सकता है।

हां! माओवादी किसी भी प्रकार के विकास का विरोध करते रहेंगे

बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने 25 नवम्बर 1949 को संविधान सौंपने के पूर्व राष्ट्र को चेतावनी देते हुए कहा था कि हमें निकटतम भविष्य के मध्य आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी का खात्म कर लेना होगा नहीं तो विषमता से पीड़ित जनता लोकतंत्र के परखचे उड़ा सकती है। अतः लोकतंत्र की सलामती के लिए जरुरी था लोगों के विभिन्न तबकों के मध्य शक्ति के स्रोतों का वाजिब बंटवारा किया जाता,जो स्व-वर्णवादी हित से प्रेरित सवर्ण-प्रधान शासक दलों ने नहीं किया और बाबा साहेब की भविष्यवाणी सत्य का होने का मौका दे दिया। इसका सद्व्यवहार किया सवर्ण मार्क्सवादियों ने। उन्होंने विषमता से पीड़ित आदिवासियों को लेकर भारतीय लोकतंत्र को विस्फोटित करने की योजना पर काम करना शुरू किया और 2009 में एलान कर दिया-'हम 2050 तक लोकतंत्र के मंदिर पर बन्दूक के बल पर कब्जा जमा लेंगे।

बहरहाल लगभग पांच दशकों से जारी माओवादी अभियान का चाल-चलन देखकर यह बात दावे से कही जा सकती है कि उनका लक्ष्य गरीब-वंचितों का भला करना नहीं ,बल्कि वंचना और गरीबी को हथियार बनाकर अपनी फौज खड़ी करनी है जो एक दिन भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर कब्जा जमा सके। ऐसा करके वे दिखाना चाहते हैं कि सारी दुनिया में ही लगभग इतिहास का पन्ना बन चुना मार्क्सवाद अंततः भारत में जिन्दा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्हें चाहिए विशाल फौज और फौज के लिए चाहिए अत्याधुनिक हथियार तथा हथियार के लिए चाहिए अपार धन(पढ़ें आठवें अध्याय के लेख-1-माओवादी किसी भी प्रकार के विकास का विरोध करते हैं, 2-बस्तर में चलती हैं जनताना सरकारें)। जिस जंगल,जल,जमीन के हक के लिए वे हथियारबंद हैं, उन्ही पर निर्माण जारी रखने के एवज में वे निजी घरानों व सरकारी महकमों से मोटी रकम वसूलते हैं। एक-एक माओवादी जोन की कमाई करोड़ों में है। हिस्सा आन्ध्र प्रदेश और बंगाल में बैठे आकाओं के पास भेजा जाता है। लगभग तमाम माओवादी नेताओं के पास महानगरों में आलीशान फ्लैट्स और भारी बैंक बैलेंस है। स्थानीय लोगों की भूमिका महज हमलों के वक्त संख्या बढाने,

माओवादियों के हथियार ढ़ोने और छुपाने ,दस्तों के लिए आसपास के गाँवों से भोजन जुटाने तक सिमित है। ऐसे में जबकि यह तय है कि गरीबी और अभाव ही इनके मंसूबा पूरा करने के माध्यम हैं तो वे कैसे नहीं विकास को रुद्ध करेंगे। वे करेंगे। हां कुछ निर्माण कार्य भी होने देंगे ताकि करोड़ों की वसूली होती रहे। किन्तु आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी के खात्मे का जो मुख्य आधार है, शक्ति के स्रोतों का वाजिब बंटवारा, वह तो नहीं होने देंगे। पर, यदि सरकार वाकई लोकतंत्र के मंदिर को सुरक्षित रखना चाहती है तो उन तबकों-दलित, पिछड़े और मुसलमान—को शक्ति से लैस कराये जो अभी तक थोक भाव से माओवादियों के चंगुल में फंसने की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। इनको शक्ति से लैस करने का एकमात्र उपाय है डाइवर्सिटी। इस डाइवर्सिटी का लाभ प्राथमिकता के साथ उन आदिवासियों को देना होगा जो अभी तक माओवादियों के चक्कर से दूर हैं। यदि माओवादियों से अछूते भूरि-भूरि आदिवासियों को एक पालिसी के तहत सप्लायर, डीलर, ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर इत्यादि बनने का अवसर मिलता है,उन्हें देखकर माओवादियों के गिरफ्त में फंसे दूसरे आदिवासियों में एक अलग आकांक्षा पनपेगी और वे खुद को उनके चंगुल से मुक्त करने के लिए विद्रोह कर देंगे। बहरहाल अब माओवादी/मार्क्सवादियों पर ज्यादा कुछ कहने-सुनने से उब पैदा होती है इसलिए इस प्रसंग को यहीं रोक कर आगे बढ़ता हूँ।

बायो डाइवर्सिटी की अनदेखी का तो यह परिणाम एक दिन आना ही था।

इस वर्ष बरसात में उत्तरखंड में बादल फटने से हुई विभीषिका को अभी भी लोग भूल नहीं पाए हैं। अच्छा लगा लोगों को यह समझते देर नहीं लगी कि विभीषिका का प्रत्यक्ष कारण ग्लोबल वार्मिंग है,जिसके पीछे है प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुन दोहन में हुई जैव-विविधता की अनदेखी हैं। खुशी की बात है कि भयावह नुकसान को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय जगत विगत बीस वर्षों से जैव-विविधता को बचाने में जुट गया है,जिसमें भारत भी पीछे नहीं है। उत्तराखंड की विभीषिका ने जैव-विविधता की रक्षा के प्रति भारतीयों को और जागरुक बनाया है। अफसोस की बात है कि विदेशियों से जैव-विविधता की रक्षा का पाठ पढ़कर हम पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने में तो योगदान कर रहे हैं, पर विदेशियों से हम सामाजिक और लैंगिक विविधता को सम्मान देने तमीज बिलकुल ही नहीं सीख पाए हैं। यह पाठ भारतीय कब सीखेंगे, कहना मुश्किल है।

डिक्की वालों को आरक्षण विरोध से बाज आना चाहिए

2005 में स्थापित दलित उद्यमियों का संगठन डिक्की उभार पर है और पूरे दलित समुदाय की शुभकामनाएं इसके साथ हैं। दलित उद्यमियों को समाज ने अपने नए नायक के रूप में वरण किया है। इसिलए सातवें डाइवर्सिटी डे में हमने डिक्की के

अध्यक्ष मिलिंद काम्बले को मुख्य अतिथि बनाकर खुद को धन्य महसूस किया। इसी तरह इस वर्ष जब दलित उद्यमी मिलिंद काम्बले और कल्पना सरोज को पद्मश्री सम्मान मिल पूरे समाज ने जश्न मनाया। किन्तु भारी दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि डिक्की वालों के तरफ से यह सन्देश जा रहा है कि दलित बिना आरक्षण के भी करोड़पति बन सकते हैं। वैसे तो न्यायपालिका,मीडिया और तमाम सवर्ण समाज ही आरक्षण के खात्मे की दिन-रात जुगत भिड़ाने मे लगा है। यदि डिक्की वालों के तरफ से यह सन्देश बड़े पैमाने पर फैल गया कि दलित बिना आरक्षण के सहारे भी ऊंचाई पर जा सकते हैं तो आरक्षण विरोधियों को अपना मंसूबा पूरा करने में और आसानी हो जाएगी। वैसे डिक्की वाले खुद भी आरक्षण पर निर्भर हैं। वे विभिन्न प्रदेशों के इंडस्ट्रियल जोन में अपने लिए भूखंड आरक्षित करने की मांग उठा रहे हैं। लघु व मध्यम उद्यमियों में दलित उद्यमियों से सरकार ने 4 प्रतिशत जो खरीद सुनिश्चित की है ,उसका लाभ उठाने के लिए वे दिन-रत एक किये जा रहे हैं। सरकार के बिना सरंक्षण के उनका भी भवष्य सुरक्षित नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की अहमियत नकारने से बचना चाहिए।

क्षेत्रीय विविधता की अनदेखी का परिणाम : तेलंगाना

केंद्र की संप्रग सरकार द्वारा तेलंगाना राज्य के गठन को हरी झंडी दिखाए जाने के साथ ही भारत में राज्यों की संख्या 29 तक बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केंद्र के इस फैसले के बाद विदर्भ राज्य की मांग जोर पकड़ने लगी है । पश्चिम बंगाल में 106 साल से अलग गोरखालैंड की मांग भी तेज हो गयी है। पश्चिम बंगाल में कामतापुर स्टेट बनाये जाने की मांग अब और जोर पकड़ेगी। तेज होगी गुजरात में अलग सौराष्ट्र बनाने की मांग। उत्तर प्रदेश के चार हिस्से में बंटवारे की मांग को अब और बल मिलना लाजिमी है। बहरहाल हम इस पर विस्तार से कुछ कहना नहीं चाहते । 2008 के इयर बुक में इस मसले पर सैकड़ों पन्ने रंगे गए थे। अब इस अप्रिय स्थिति पर इतना ही कहना है कि हर बात में अमेरिका की नकल करते रहने वाले भारत की शासक जमात वहां की सामाजिक और लैंगिक विविधता के साथ क्षेत्रीय विविधता को भी अपनाये। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आनेवाले दिनों में पहले से विच्छिन्न भारतीय समाज और विच्छिन्नता का शिकार होगा तथा देश में अनेकों तेलंगाना वजूद में आएंगे। यदि इस अप्रिय स्थिति से बचना है तो शासक दलों को अध्ययन करना पड़ेगा क्यों 200 साल पहले 50 राज्यों में विभाजित अमेरिका आज भी 50 राज्यों तक ही सिमित है।

आशा की नई किरण : उप्र का बहुजन छात्र-आन्दोलन

बहुजन नेतृत्व की सवर्ण-परस्ती तथा सवर्णवादी न्यायपालिका-मिडिया के बहुजन

विरोधी रुख से हताश-निराश बहुजन समाज को इस वर्ष जुलाई में शुरू हुए बहुजन-छात्र आन्दोलन में ही उम्मीद की रोशनी दिखाई पड़ी है। इस समय जबकि भाजपा और कांग्रेस जैसी दो सबसे बड़ी सवर्णवादी पार्टियाँ जोर शोर से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं,बहुजन नेतृत्व खामोस है। साफ दिखता है कि उनके पास अपने समाज के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। इनमें कुछ अपना वजूद बचाने के लिए तो कुछ प्रधानमंत्री बनने के अपने व्यक्तिगत एजेंडे पर अपनी गतिविधियाँ चला रहे हैं। ऐसे में उन्होंने खुद ही अपने को समाज से अलग-थलग कर जहां एक नए नेतृत्व के लिए मैदान साफ कर दिया है वही दूसरी ओर दोनों सवर्णवादी दलों को भी अपना गेम खेलने के लिए फ्री कर दिया है। कुल मिलाकर सही नेतृत्व के अभाव में बहुजन भारत का राजनीतिक का माहौल बहुत निराशाजनक हो गया है। ऐसे में इलाहाबाद से शुरू हुए आरक्षण समर्थक छात्र आन्दोलन में बहुजन बुद्धजीवियों को भविष्य का एक बेहतर विकल्प दिखने लगा है।

इस आन्दोलन के पृष्ठ में है उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की नई आरक्षण नीति ,जिसके तहत सामान्य श्रेणी के 50 प्रतिशत सीटों पर भी उन उन छात्रों को शामिल करने का प्रावधान था जो सामान्य के लिए निर्धारित 'कटऑफ' के बराबर या उससे ज्यादा अंक पाते। नई आरक्षण पद्धति के तहत आरक्षित वर्ग के 76 प्रतिशत छात्रों का चयन हो गया था। किन्तु सरकार ने आरक्षण विरोधी सवर्ण छात्रों के दबाव में नई आरक्षण नीति वापस ले ली, जिससे क्षुब्ध होकर बहुजन समाज के छात्रों ने आन्दोलन छेड़ दिया है। इस आन्दोलन की खासियत यह है कि छात्र जहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो प्रमुख स्तम्भों (माया-मुलायम) को नकार रहे है वहीं कांशीराम को अपना आदर्श मानते हुए उनके भागीदारी दर्शन-जिसकी जीतनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी-को मूलमंत्र मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनका एजेंडा सिर्फ आयोग की नौकरियों तक सिमित न रह कर हर क्षेत्र में संख्यानुपात में भागीदारी तक प्रसारित है। इनके एजेंडे को देखकर लगता है कि भारत के इतिहास में इतना व्यापक लक्ष्य को लेकर अब तक कोई छात्र आन्दोलन संगठित नहीं हुआ। इस बीच छात्रों ने 17 सितम्बर को आरक्षण पर इलाहाबाद में महापंचायत बुलाई किन्तु सरकार ने इस पंचायत में भाग ले रहे शरद यादव,उदित राज,अनुप्रिया पटेल सहित अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर पंचायत पर रोक लगा दी। बाद में पुनः उन्होंने 20 अक्तूबर को आजमगढ़ में वैसी ही महापंचायत बुलाई। इस बार भी सरकार ने पहले की भांति नेताओं को गिरफ्तार कर पंचायत को विफल करने का प्रयास किया। फिलहाल सरकार का इस आंदोलन को कुचलने का अभियान जारी है। किन्तु छात्रों का संकल्प भी अडिग है। इस आन्दोलन को आगे बढ़ाते हुए दिनेश सिंह यादव,लालाराम सरोज, मनोज यादव इत्यादि ने नए बहुजन नायकों के उभरने का संकेत दे दिया है। इस अभूतपूर्व आन्दोलन का हर कदम पर दिलेरी से समर्थन कर अनुप्रिया पटेल मंडल-3 की

महानायिका के रूप में उभरी हैं। इनका हर तरह से समर्थन कर बीडीएम से जुड़े लोग खुद को धन्य मह्सून करते हैं।

हर बार की तरह इस बार भी इयर बुक का खास आकर्षण साक्षात्कार है। इस बार यह पूरी तरह मार्क्सवादियों पर केन्द्रित है,जिसके पृष्ठ में 12-16 मार्च,2013 तक चंडी गढ़ के भकना भवन में आयोजित मार्क्सवादियों की संगोष्ठी है। उस संगोष्ठी में उन्होंने बुद्ध और बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर को पूरी तरह से खारिज कर 'जाति उन्मूलन की समाजवादी परियोजना' प्रस्तुतु किया। जिन मार्क्सवादियों ने जाति प्रश्न की बराबर उपेक्षा की उनके द्वारा जाति उन्मूलन की परियोजना पेश करना निश्चय ही चौकाने वाला काम था। बहरहाल जाति उन्मूलन के लिए समाजवादी परियोजना के मुकाबले डाइवर्सिटी केन्द्रित आंबेडकरवादी परियोजना कितनी प्रभावी है,यह जानने के लिए पाठकों को साक्षात्कार अध्याय प्रचुर समान मुहैया कराता है । इसके लिए साक्षात्कार में शामिल डॉ. विजय कुमार त्रिशरण, मा. मनोज कुमार, मा. मूलचंद सोनकर, मा. शीलबोधि, मा. जवाहरलाल कौल 'व्यग्र', मा. बुद्ध शरण हंस, मा. मुसाफिर बैठा, डॉ. अजय यतीश के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। चंडीगढ़ में मार्क्सवादियों ने बुद्ध और बाबा साहेब को खारिज करने का जो बौद्धिक दुःसाहस दिखाया है उसका मुकम्मल जवाब देने के लिए संगठन ओर से 'जाति उन्मूलन : मार्क्सवादी बनाम आंबेडकरवादी परियोजना' नामक 264 पृष्ठीय पुस्तक प्रकाशित की गयी है। डाइवर्सिटी समर्थकों के लिए यह एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक साबित हो सकती है।

फेसबुक पर दुसाध

गत वर्ष के इयर बुक में मैंने स्वीकार किया था कि फेसबुक से जुड़कर भी मैं इसलिए दूर हो गया क्योंकि उस पर 100-200 शब्दों की टिप्पणियों के लिये लगभग उतनी ही उर्जा लगती थी ,जितनी हजार शब्दों के लेख पर । किन्तु गत अक्तूबर में मेरे बेटे कविश ने नए सिरे से फेसबुक से जुड़ने के लिए आग्रह किया,जिसे मैं टाल न सका। सप्ताह भर बाद ही इतना मजा आने लगा कि हर 4-5 घंटे पर फेसबुक नहीं खोलने पर बेचैनी महसूस होने लगी। मैं साल भर से फेसबुक को खूब इंज्वाय कर कर रहा हूँ। परिणामस्वरूप इतनी सामग्री जमा हो गई कि उसे प्रकाशित करने के लिए बाकायदे एक अध्याय की जरुरत पड़ गयी। उम्मीद है पाठक बन्धु फेसबुक पर दुसाध को झेल लेंगे। हां, मैं तमाम पाठक बंधुओं को फेसबुक से जुड़ने की भी गुजारिश करता हूँ। इस बार बुद्ध शरण हंस का बिजनेस टिप्स तथा प्रभुलाल अंजाना का बेरोजगारी : समस्या और समाधान पाठकों के लिए स्पेशल साबित होंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।

सोलहवी लोकसभा चुनाव के मुद्दे

सोलहवीं लोकसभा चुनाव के अनुष्ठित होने में अब कुछ ही माह रह गए हैं. उससे पूर्व यह वार्षिकी आपके हाथों में जाने के कुछ ही दिन बाद ही केंद्र की सत्ता दखल की लड़ाई का सेमी-फाइनल कहे जानेवाले पांच राज्यों के चुनाव शुरू हो जायेंगे. बहरहाल सोलहवीं लोकसभा के लिए राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है. इनका रंग-ढंग देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि भारत में भीषणतम पैमाने पर फैली आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी इनके लिए कोई समस्या है. अगर ऐसा होता तब मतदाताओं के बीच ऐसे प्रोग्राम लेकर जाते जिससे शक्ति के स्रोतों के अत्यंत असमान बंटवारे पर अंकुश लगता.इसके बजाय चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष ,सभी राहत और खैरातनुमा घोषणाओं के सहारे चुनाव जीतने की जुगत भिड़ा रहे हैं.ऐसे में लगता है कि विगत चुनावों की भांति इस बार भी वे प्रायः मुफ्त में अनाज, टीवी-फ्रिज-कम्प्यूटर, साइकल के बदले वोट खरीदने की रणनीति पर काम कर रही हैं. अगर ऐसा होता है तो हम अतीत की भांति एक और मुद्दा विहीन चुनाव देखने के लिए अभिशप्त होंगे. अतः हमें कुछ ऐसा करने में सर्वशक्ति लगानी होगी जिससे वे शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता का लागू कराने की घोषणा में एक दूसरे से होड़ लगावें. भारी संतोष की बात है कि जहाँ हमारी राजनीतिक पार्टियां राहत और भीखनुमा घोषणाओं से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, दलित संगठन अमूर्त मुद्दों से आगे निकल कर अपना एजेंडा अर्थोपार्जन के स्रोतों के वाजिब बंटवारे पर खड़ा कर रहे हैं. इसका नया दृष्टान्त पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पेश एक नया 'दलित दस्तावेज' है. (देंखे पृष्ठ-356)

अंत में। आभारी हूँ उन पत्र-पत्रिकाओं का जिनमें छपे लेखों से इयर बुक : 2013-14 समृद्ध हुई है। आभारी हूँ लेखक बंधुओं का जिनके लेखों के बिना यह अंक बेजान लगता। हर बार की तरह एक बार फिर डाइवर्सिटी मूवमेंट को तन-मन-धन से आगे बढानेवाले मा. बुद्ध शरण 'हंस', डॉ. संजय पासवान, मा. छेदी पासवान, डॉ. विजय कुमार त्रिशरण, मा. दिलीप मंडल, मा. बृजपाल भारती, मा. ललन कुमार, मा. अभिजित कुमार, डॉ. राजीव, डॉ. राज बहादुर मौर्य, मा. शीलबोधि, मा. सुरेश पंडित, प्रो. आईजे सिंह, मा. नागेन्द्र कुमार, डॉ. कौलेश्वर प्रियदर्शी, मा. निर्मल पासवान, मा. आशिक भागलपुरी, डॉ. सुदर्शन, इंजी. हरिकेश्वर राम, इंजी. हीरालाल, मा. वीके पाल को अशेष धन्यवाद, जिनके सहयोग से नियमित अंतराल पर डाइवर्सिटी साहित्य लोगों के बीच पहुँच रहा है।

!! जय भीम-जय भारत !!

आठवां डाइवर्सिटी डे	एच एल दुसाध
(8 नवम्बर, 2013)	(संपादक, डाइवर्सिटी इयर बुक)

अनुक्रम

सम्पादकीय : डाइवर्सिटी इयर बुक : 2013-14 5

अध्याय-1
मिशन डाइवर्सिटी

रिपोर्टः बहुजन डायवर्सिटी मिशन का सातवां डायवर्सिटी दिवस
—बुद्ध शरण हंस 27
बहुजन डायवर्सिटी मिशन का सातवां स्थापना दिवस समारोह 36
—प्रस्तुति : बुद्ध शरण हंस 36
बीडीएम के सातवें स्थापना दिवस समारोह पर कविश कुमार की रिपोर्ट 40
डाइवर्सिटी डे—एच. एल. दुसाध 42
डाइवर्सिटी मैन ऑफ वर्ल्ड : नामदेव ढसाल—एच एल दुसाध 45
हंस का बिजनेस टिप्स
डायवर्सिटी को समझिये और अमल कीजिए—बुद्ध शरण हंस 48
मसाले का कारोबार—बुद्ध शरण हंस 50
ठीकेदारी अर्थोपार्जन का बेहतर साधन—बुद्ध शरण हंस 52
खाद्य व्यापारी बनकर सम्पन्न बनें—बुद्ध शरण हंस 55
कम्पनी कानून का विशेषज्ञ बनना बेहतर—बुद्ध शरण हंस 59
बाजार में हम कहां हैं?—बुद्ध शरण हंस 61
नए साल 2013 की मंगल कामना—बुद्ध शरण 'हंस' 68
नव-वर्ष का हमारा संकल्प : आर्थिक और सामाजिक विषमता का खात्मा 71
—एच. एल. दुसाध 71
पुस्तक समीक्षा
हिन्दू संस्कृति पर दलित नजरिया—कुमार मुकुल 74
हिन्दुत्त्व मुझे क्यों अस्वीकार है—सुरेश पंडित 76

अध्याय-2
प्रमोशन में आरक्षण

कोटा बिल की पहली बाधा पार 87
प्रमोशन में आरक्षण मंजूर नहीं : अजित 88

कोटा बिल के विरुद्ध अब वरूण ने भी उठायी आवाज 89
'आरक्षण विरोधी कदम उठाकर मुलायम ने दिल जीता' 89
गुमराह न करे भाजपा : सर्वजन समिति अगला आन्दोलन 'करो या मरो' 90
आरक्षण समर्थकों का आन्दोलन होगा तेज 92
प्रोन्नति में आरक्षण प्रावधान और व्यावधान 93
योग्यता, अवसर और आरक्षण—प्रो. आनंद कुमार 94
वंचितों के साथ न्याय की दरकार—गंगा सहाय मीणा
विधान और प्रावधान—अनुप सुरेन्द्रनाथ 99
प्रमोशन में आरक्षण 1969 से ही—डॉ. लालाजी प्रसाद निर्मल, 103
जरूरी है प्रमोशन में कोटा—जीतेन्द्र मीणा 105
सरकारी सेवाओं में आरक्षण का मुद्दा और संविधान संशोधन
—मोहनसिंह 107
प्रमोशन में आरक्षण ठीक नहीं—विनय कटियार 110
नीतिगत फैसले में एसटी/एसटी की भूमिका जरूरी—अनिल शास्त्री 110
सामान्य वर्ग के लिए हो अलग पोस्ट—वासुदेव आचार्य 111
हंगामे के बीच विधेयक लाना उचित नहीं—डी.राजा 112
कटुता नहीं बढ़नी चाहिए—मुख्तार अब्बास नकबी 113
आरक्षण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया—डॉ. विवेक कुमार 114
भेदभाव मिटेगा नहीं, बढ़ेगा—शैलेन्द्र दुबे 118
अन्य समूहों को भी दें प्रगति के मौके—के. विक्रम राव 120
पदोन्नति में आरक्षण : कुछ सवाल—कंवल भारती 123
लोकतंत्र में बाधक : दैविक-अधिकारवादी मानसिकता—एच. एल. दुसाध 126
बहुजन समाज बनाने की नई पहलकदमी की जरूरत—एच. एल. दुसाध 130
रोजगार है, पर उम्मीदवार नहीं—राजकिशोर 132

अध्याय-3
दिल्ली गैंग रेप

कब रूकेगा यह सिलसिला सिर्फ बातों की सरकार—नीलू रंजन 135
फिर भी बढ़ रहे हैं रेप केस 136
गंभीर मामलों में होगी फांसी! 137
महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया चार्टर 139
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश 140
यौन अपराधों के लिए सख्त कानून आज से 142

गैंग रेप बुद्धिजीवियों की राय में
अभूतपूर्व राष्ट्रीय शर्मिंदगी—सी. उदय भाष्कर 143
फांसी दो- फांसी दो, पर किस- किसको—विभांशु दिव्याल 145
कुछ जिम्मेदारी हमारी भी—नदीम 147
परत दर परत—राजकिशोर 149
इस जनाक्रोश को अंजाम का इंतजार—किरण बेदी 151
मृत्युदंड समाधान नहीं—जयसिंह रावत 154
स्त्री का चरित्र किसी घटना से न आंका जाए—उदित राज 157
बदलाव चाहने वालों के नाम खुली पाती—चेतन भगत 160
अधिकारों के लिए लड़नी होगी चौतरफा जंग—अनिल शुक्ल 162
इस आंदालन के निहितार्थ—आनंद प्रधान 164
मध्यम वर्ग को चाहिए अपनी एक पार्टी—टोनी जोसेफ 169
इस आंदोलन से कितनी उम्मीद—योगेंद्र यादव 171
बलात्कार विरोधी कानून : हवाओं में घुलता जहर—अश्विनी कुमार 173
मोमबत्तिया आंदोलनों से कुछ नहीं होगा—विभांशु दिव्याल 175
मीडिया मॉब—सुधीश पचौरी 177
मीडिया के सरोकार पर उठते सवाल—राममोहन पाठक 179
बजट तक पहुंची 'निर्भया' की गूंज—अंजलि सिन्हा 182
क्योंकि भारत की हिंदी पट्टी आज भी मध्य युग में वास करती है 184
—एच. एल. दुसाध 184
भारतीय राज्य पर कब्जा जमाने का भयावह मंसूबा—एच. एल. दुसाध 190
एक ऐतिहासिक प्रायश्चित की जरूरत—एच. एल. दुसाध 192

अध्याय-4
दोबारा ओबामा

दोबारा ओबामा 196
ओबामा फिर एक बार 197
बेहतरीन वक्त आना अभी बाकी : ओबामा 198
बदलते अमेरिका की निशानी—प्रो. विवेक कुमार 201
काश, अमेरिका से कुछ सीखते—विभांशु दिव्याल 204
ओबामा पर अमेरिका की मुहर—पुष्पेश पंत 206
ये उम्मीद की जीत है—उपेन्द्र राय 208
पुनर्निर्वाचित ओबामा की यह तन्मयता—राजकिशोर 211

Continue Your Reading Journey

This preview has ended. Access the complete library and support our mission.

Join Our Inclusive Reading Community

- ✓ We champion diverse voices and perspectives
- ✓ Your support helps amplify underrepresented authors
- ✓ We provide free access to educational institutions
- ✓ Building bridges through shared stories
- ✓ Creating space for all narratives to be heard

Support Our Mission

Your donation enables us to:

- Curate diverse book collections
- Support authors from marginalized communities
- Provide free resources to educators
- Maintain our accessible digital library

Visit: www.diversitymission.in

Sign the diversity pledge • Make a donation • Download full library